साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 3-9 अप्रैल, 2023, 2023, वर्ष-8, अंक-51

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

» पीएम मोदी बोले- मध्यप्रदेश निरंतर लिख रहा विकास की गाथा

» कहा-मैं इतने कम अंतराल में दूसरी बार मध्यप्रदेश आया हूं

-पीएम ने देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

उमंग-तरंग और आत्मविश्वास का प्रतीक नए इंडिया की 'वंदे भारत'

-पहले ट्रेनों को रोकने की होती थी मांग पर अब नई वंदे भारत की डिमांड

-सीएम ने कहा-बदलता भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विजन का चमत्कार

-रेल मंत्री बोले-मप्र के 80 रेलवे स्टेशनों को बनाया जा रहा है वर्ल्ड क्लास

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश निरंतर विकास की गाथाएं लिख रहा है। खेती, उद्योग, गरीबों के लिए घर, हर घर जल से नल, गेहूं उत्पादन आदि अनेक क्षेत्रों में प्रदेश अग्रणी है। पहले बीमारू कहा जाने वाला राज्य आज हर क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। हमें विकसित भारत में मध्यप्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। नई वंदे भारत ट्रेन इसी संकल्प का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत में नई व्यवस्था, नई परंपरा बन रही है। वंदे भारत ट्रेन नए भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। यह भारत की आधुनिकतम ट्रेन है, जिसके लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री इतने कम अंतराल में किसी रेलवे स्टेशन पर दोबारा किसी कार्यक्रम में आया है। मैं पहले रानी कमलापति स्टेशन के लोकार्पण पर आया था और आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्रेन के प्रथम कोच में जाकर स्कूली बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ड्राइविंग कैब के क्रू मेम्बर्स के साथ भी संवाद किया।

स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट योजना से कारीगरों के कपड़े, कलाकृतियों, पेंटिंग्स, बर्तन इत्यादि का विक्रय के लिए पूरे भारत में 600 से अधिक आउटलेट रेलवे स्टेशन पर खोले हैं, जिसका लाभ आज लाखों लोग ले रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है, 6 हजार रेलवे स्टेशन वाईफाई है और 900 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी का काम पूरा हो गया है। वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में सुपरहिट रही है और हर कोने से इन्हें चलाने की मांग आ रही है।

मेड इन इंडिया कवच

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। पुरानी सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते रेलवे का आधुनिकीरण नहीं किया। वर्ष 2014 तक नॉर्थ ईस्ट रेलवे से नहीं जुड़ा। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसे रेलवे से जोड़ा और रेलवे का कायाकल्प किया। आज भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का श्रेष्ठ नेटवर्क है। पहले हजारों मानवरहित फाटक थे, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। आज पूरा ब्रॉडगेज मानव रहित, फाटक मुक्त है। रेल यात्री सुविधा को हमने मेड इन इंडिया कवच प्रणाली से लैस किया है। तकनीकी का प्रयोग कर शिकायतों का निराकरण किया गया है।

रेलवे के बजट में भी रिकॉर्ड वृद्धि

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के बजट में भी रिकॉर्ड वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2014 से पहले मध्यप्रदेश का रेलवे बजट औसतन 600 करोड़ हुआ करता था, जो अब बढ़ कर 13000 करोड़ हो गया है। मध्यप्रदेश सहित देश के 11 राज्यों में रेलवे ट्रेक का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार वर्ष 2014 से पहले 600 किलोमीटर प्रति वर्ष थी, अब वह बढ़कर 6000 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है।

वैष्णव बोले-मप्र में 80 स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास

जन सुविधाएं डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किए है। विशेष रूप से मप्र में रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विजन के परिणाम स्वरूप बहुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश भर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प की सिद्धि में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का अहम स्थान है। इस स्टेशन के आधुनिकीकरण से जो अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। मप्र में 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम जारी है। जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, यह डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है।

सीएम बोले-पीएम ने दी वंदे भारत की सौगात

मध्यप्रदेश के सौभाग्य का फिर से उदय

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सौभाग्य का फिर से उदय हुआ है। प्रधानमंत्री फिर से हमारे प्रदेश आए। जो कभी पिछली सरकारों में गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको वर्ल्ड क्लास शानदार रेलवे स्टेशन में बदला गया है, यह मोदी विजन है। प्रधानमंत्री पहली बार आए तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन किया गया, और आज यह वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। ससे हम भोपाल से दिल्ली कम समय में पहुंच सकेंगे। पिछली सरकारों ने हमें विदेशी तंत्र दिया था। प्रधानमंत्री ने देश को स्वेदशी का मंत्र दिया है। वंदे भारत रेल पूरी तरह से स्वदेशी है। पीएम के नेतृत्व में पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश भी बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे नशे पर नियंत्रण भी मोदी विजन का ही एक मंत्र है। इस दिशा में आज से मप्र में शराब की दुकानों के साथ चलने वाले अहाते बंद कर दिए गए हैं।

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक

प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के साथ जिन क्षेत्रों में नवीन परियोजनाएं आरंभ हो रही हैं, वहां किसानों को नहरों के रख-रखाव और पानी की हर बूंद के सही उपयोग के संबंध में जागरूक करना आवश्यक है, जिससे हम अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग उत्पादन में कर सकें। मुख्यमंत्री वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की मंत्रालय में हुई 119वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खंडवा में 8 हजार हेक्टेयर में होगी सिंचाई| खण्डवा जिले की खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना फेस-2 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से खण्डवा जिले के 7 हजार 910 हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। मण्डला जिले को लाभान्वित करने वाली हालोन सिंचाई परियोजना के शेष कार्यों और बरगी व्यपवर्तन परियोजना के संबंध में भी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई।

परियोजना को स्वीकृति

बैठक में एक हजार 11 करोड़ रुपए की बहोरीबंद और 720 करोड़ की शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। बहोरीबंद परियोजना से कटनी जिले के 151 गांव में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहीद इलाप सिंह परियोजना से हरदा जिले के 118 गाँव के 26 हजार 890 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

रीवा-सतना बढ़ेगा सिंचाई का रकबा

बाणसागर जलाशय से निकली बहुती नहर परियोजना के शेष निर्माण कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई। बहुती नहर से रीवा और सतना जिले के 383 ग्राम के एक लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध होगी। सतना जिले के विकासखण्ड मझगवां में पैसूनी नदी पर प्रस्तावित दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। परियोजना से सतना जिले के विकास खण्ड मझगवां के पहाड़ी क्षेत्र के 15 गांव लाभान्वित होंगे।

शिवराज ने कहा-चंबल का विकास और जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता

अटल एक्सप्रेस-वे: रि-सर्वे करें ताकि किसानों की कीमती जमीन न जाए

केन्द्रीय मंत्री बोले-अटल एक्सप्रेस-वे बनने से अंचल का तेजी से होगा विकास

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल क्षेत्र का विकास और जनता का कल्याण राज्य शासन की प्राथमिकता है। विकास में चंबल क्षेत्र पीछे न रहे, इसलिये अटल एक्सप्रेस-वे श्योपुर, मुरैना, भिंड से निकाला जा रहा है। इस पर करीब 8 हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वे के निर्माण के लिए किए गए सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि कई किसानों की कीमती जमीन इसमें आ रही है। इसलिए रि-सर्वे कराया जाए, जिससे किसानों की कीमती जमीन नहीं जाए। उल्लेखनीय है कि 308 किलोमीटर लंबे इस वे के निर्माण से चंबल क्षेत्र का उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बेहतर संपर्क हो जाने से विकास में गति आएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वे में अधिक से अधिक सरकारी जमीन का उपयोग हो। जमीन का पुन: चिन्हांकन करें, जिससे किसानों की जमीन वे में नहीं जाए। अटल एक्सप्रेस- सर्वे कार्य भी इसी दृष्टि से किया जाए।

छोटे किसानों की संख्या ज्यादा

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। छोटे किसानों के लिये 2-4 बीघा जमीन अत्यंत उपयोगी है। अटल एक्सप्रेस-वे के बनने में अगर छोटे किसानों की जमीन उसमें जाती है, तो उनके लिये कठिनाई होगी। यह आवश्यक है कि छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये अटल एक्सप्रेस-वे का रि-सर्वे कराया जाए। किसान हितैषी मुख्यमंत्री की पहल से अंचल में अनेक विकास कार्य हुए हैं। अटल एक्सप्रेस-वे भी क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के बनने से छोटे और मध्यम उद्योग लगेंगे, जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

बेटे-बेटियों को रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस से केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अटल एक्सप्रेस-वे के संबंध में चर्चा की। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई मंत्रालय से और चंबल कमिश्नर सहित मुरैना, भिंड एवं श्योपुर कलेक्टर वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के बनने से उद्योगों के साथ किसान भी अपनी खेती कर सकेंगे। साथ ही नए-नए उद्योग प्रारंभ होने से बेटे-बेटियों को रोजगार मिलेगा और विकास के द्वार तेजी से खुलेंगे।

लोगों को सुविधा होगी

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में सबलगढ़ से करोली जाने के लिए अटारघाट पुल बन कर तैयार हो गया है। पुल निर्माण से करोली जाने के लिए लोगों को सुविधा होगी। लोगों को अब मुरैना, धौलपुर, बाड़ी होकर करोली नहीं जाना पड़ेगा और वे इस पुल से शिवपुरी से सबलगढ़ और करोली पहुंच सकेंगे। विधायक सूबेदार सिंह रजौधा एवं जौरा क्षेत्र के किसान भी वर्चुअली शामिल हुए।

मौसम में आने वाले इस बदलाव से किसान परेशान

लवकुश नगर और चंदला में ओलावृष्टि, खेतों में बिछ गई गेहूं की फसल

छतरपुर। लवकुश नगर में अचानक से मौसम बदला और तेज हवा चली। इसके साथ बारिश हुई और ओले बरसे। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह 250 ग्राम वजन तक के ओले गिरे हैं। इसके साथ ही चंदला में भी ओलावृष्टि होने से एक दर्जन से ज्यादा गांवों में नुकसान है। चंदला और लवकुश नगर में ओलावृष्टि से गेहूं और दलहनी फसल खेतों में बिछ गई है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर राहत की मांग की है।चंदला और लवकुश नगर के गौरिहार, बछौन, कटहरा, सिल्पतपुरा, कटिया, देवरी, बगमऊ, बलकौरा, माधवपुर, काछिनपुरवा सहित एक दर्जन से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि हुई है।

दस मिनट तक ओलों की बरसात- कटहरा में 10 मिनट तक ओले बरसे। इससे जमीन पर ओलों की सफेद चादर सी बिछ गई। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि से वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब परिवार को पालने के लिए भी भीख मांगने की नौबत आ गई है। वहीं ओलावृष्टि की जानकारी मिलने पर एसडीएम निशा बांगरे ने पटवारियों को गांवों में जाकर नुकसान की जानकारी

भेजने के लिए कहा है। एसडीएम ने बताया कि ओलावृष्टि की जानकारी मिली है। गौरिहार, चंदला, लवकुशनगर के गांवो में ओले गिरे हैं। गौरिहार तहसील अंतर्गत गांव सरबई, राजौरा, मालपुर, किशोरी, पुखरी, ओदी, महुई गांव में ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है।

कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा फार्म गेट एप अवॉर्ड, दी बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को फार्म गेट एप के लिए अवार्ड मिलने पर किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और कृषि विभाग को शुभकामनाएं दी। मंत्रालय में मुख्यमंत्री को कृषि मंत्री पटेल और एमडी मंडी बोर्ड जी.व्ही. रश्मि ने दिल्ली में मिला अवार्ड सौंपा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की प्रोजेक्ट केटेगरी में फॉर्म गेट एप के लिए 20वां सीएसआई-एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड-2022 प्रदान किया गया है। यह एप एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसे किसान अपने एंड्राइड मोबाइल पर नि:शुल्क डाउनलोड कर सकता है। इससे किसान अपनी मर्जी अनुसार अपनी उपज को अपने घर, खलिहान, गोदाम से विक्रय में सक्षम हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ-साथ अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर विक्रय की आजादी मिली है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश में इकलौता राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है।

आठ मंडियों में एमपी फार्मगेट एप

मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित एमपी फार्मगेट एप प्रदेश की 8 मंडियों भोपाल, हरदा, इंदौर, देवास, गुना, सागर, जबलपुर एवं सतना में 1 अगस्त, 2022 से पायलट के रूप में एंड्राइड एप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। साथ ही दिनांक 27 सितंबर, 2022 से उज्जैन मंडी को पायलट योजना में शामिल किया गया है। एमपी फार्म गेट एप का मध्यप्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में संचालन किया जा रहा है।

12981 किसानों ने किया उपयोग

एमपी फार्म गेट एप का उपयोग कर 12981 कृषकों द्वारा 64 लाख क्विंटल विभिन्न कृषि उपज विक्रय की गई है। फार्म गेट से किसानों से सीधा क्रय पूर्व में सौदा पत्रक पोर्टल के माध्यम से अप्रैल 2021 से किया गया है। वर्तमान तक कुल 91 लाख टन विभिन्न कृषि उपजों के सौदे हुए हैं। धीरे-धीरे इस एप का प्रयोग ज्यादातर किसानों द्वारा किया जाने लगा है। अब तक इस एप का उपयोग कर मंडी प्रांगण में 16 प्रतिशत तक की आबक हो चुकी है।

रीवा में 237 वैरायटी वाले आम के बागान पर सबसे खास है गोविंदगढ़ का आम

विंध्य की पहचान! रीवा के सुंदरजा आम को मिला जीआई टैग

रीवा। जागत गांव हमार

देश-विदेश में विंध्य को पहचान दिलाने वाले सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल गया है। रीवा में 237 वैरायटी वाले आम के बागान है। पर सबसे खास गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन कृषि महा विद्यालय का फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया 32 हेक्टेयर में फैला है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उपक्रम है। जीआई टैग मिल जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। रीवा के फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में आम और अमरूद पर रिसर्च की जाती है। फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया के विज्ञानी डॉ. टीके सिंह के द्वारा कुछ वर्ष पहले जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था। जिसको स्वीकार कर सुंदरजा आम को जीआई टैग दे दिया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया

एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल

सुंदरजा रीवा जिले में पाया जाने वाला विशिष्ट किस्म का आम है, इसका स्वाद सुगंध आम की सभी किस्मों से बेहतर है। यह सीमित क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन इसकी पहचान विशिष्ट है। सुंदरजा आम को रीवा जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया गया है। सुंदरजा की विशिष्ट पहचान को जीआइ टैग मिलने पर आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

मार्केटिंग के प्रयास शुरू| अब सुंदरजा आम पूरे विंध्य की पहचान बनकर दुनिया में जाना जाएगा। सुंदरजा आम की खेती और मार्केटिंग के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। परंपरागत रूप से सुंदरजा की उपज लेने वाले किसान इसकी ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं। सुंदरजा आम के क्षेत्र विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी बड़े पैमाने पर खेती होने पर यह विंध्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा।

लगातार किया प्रयास

गोविंदगढ़ और उसके आसपास पैदा होने वाली सुंदरजा आम की किस्म को जीआइ टैगिंग से किसानों में चौतरफा खुशी है। किसान का कहना है कि अब हमारे बाग का आम जीआई टैगिंग के साथ बिकेगा। ऐसे में ज्यादा भाव व बड़े बाजार मिलेंगे। शासन प्रशासन द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तब कहीं जाकर सुंदरजा आम को जीआई टैगिंग मिली है।

इन वैरायटी के आम मौजूद

रीवा के फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली के साथ-साथ ही कई राजा-महाराजाओं के नाम पर आम की किस्में मौजूद हैं।

-कैबिनेट: खंडवा-आगर मालवा-सिंगरौली में एक-एक नई तहसीलों के गठन को मंजूरी

किसानों के बैंकों की ब्याज की राशि भरने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। किसानों को राहत देते हुए बैंकों की ब्याज की राशि भरने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जिसकी आखिरी तारीख 28 मार्च थी। वहीं, भोपाल में प्रस्तावित नई तहसीलों के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि सरकार ने सहकारी बैंकों से किसानों के लिए लोन के ब्याज भरने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे एक माह में सरकार को 60 करोड का नुकसान होगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसानों के साथ सरकार खड़ी है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने प्रभार वाले जिलों में गेहूं उपार्जन पर नजर बनाए रखें। किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैठक में राजस्व विभाग ने ओलावृष्टि के नुकसान की जानकारी भी दी।

50 फीसदी तक फसल बर्बाद- कैबिनेट में सीएम ने 25 फीसदी से 33 फीसदी, 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत नुकसान को सौ फीसदी माना है। वसूली स्थगित रहेगी। उसका ब्याज सरकार भरेगी। मुआवजे के बाद किसानों को फसल बीमा का भी लाभ दिलाया जाएगा। जीरो प्रतिशत ब्याज पर अगले साल भी किसान को कर्जा मिलेगा।

पन्ना में खुलेगा कृषि कॉलेज: किसानों के बच्चों को मिलेगी ड्रोन का प्रशिक्षण

ड्रोन उड़ाने की देंगे ट्रेनिंग

सरकार किसानों के बेटों ओर नौजवानों को को डोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगी। इसके लिए तीन साल में छह हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

पन्ना को मिला कृषि कॉलेज

कैबिनेट ने पन्ना जिले में नया कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तीन साल में महाविद्यालय बनकर तैयार होगा। इसके लिए अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रुपए और आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

चचाई में नया प्लांट होगा

मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 600 मेगावाट की एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए साढ़े हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

तीन नई तहसील| कैबिनेट ने खंडवा जिले में छैगांव माखन को नई तहसील बनाने और 17 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सिंगरौली जिले के बरगवां और आगर मालवा में सोयत कला को नई तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

भोपाल में नए तहसील का प्रस्ताव होल्ड| कैबिनेट में भोपाल में चार नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री डॉ. नरोत्म मिश्रा ने बताया कि अभी भोपाल की चार नई तहसील के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया है। सीएम ने प्रस्ताव को विस्तृत तरीके रखने को कहा है।

श्योपुर को भरपूर पानी| श्योपुर जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 539 करोड़ सैच्य क्षेत्र 15 हजार 300 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मप्र में मार्च में फसलों को सूखने का ही नहीं मिला मौका

सरसों, गेहूं, लहसुन, दलहनी फसलों को हुआ नुकसान

भोपाल। जागत गांव हमार

मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा के कई दौर आ चुके हैं। फसलों के पकने के समय में वर्षा ने उत्पादन और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। रुक-रुककर मौसम बिगड़ने से फसलों को सूखने का अवसर भी नहीं मिल सका। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। ग्वालियर-चंबल अंचल में मुरैना में सरसों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहां के 17 गांवों में 3071 हेक्टेयर में सरसों की फसल को 70 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। भिंड में 1352 हेक्टेयर में सरसों, गेहूं और धनिया की फसल व शिवपुरी के पिछोर-खनियांधाना में 1230 हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हुआ है। मुरैना के जौरा निवासी शिवदयाल धाकड़ ने बताया कि ओलवृष्टि से सरसों को दाने झड़ गए वहीं खेतों में पानी भरने से दाना गलकर काला पड़ गया। गेहूं के बालियां पूरी तरह खेतों में बिछ गईं। रुक-रुककर मौसम बिगड़ते रहने से फसलों को सूखने का मौका नहीं मिल सका।

लहसुन की गुणवत्ता बिगड़ी

बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर में अंचल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम नुकसान है। मालवा-निमाड़ के कई जिलों में भी वर्षा हुई। खंडवा में बूंदाबांदी हुई। अंचल में अभी गेहूं, लहसुन की फसल खेतों में ही है या फिर कटी रखी हुई है। बीते सप्ताह हुई वर्षा से गेहूं गीला हो गया और दाने की चमक चली गई। इधर, लहसुन गीली हो जाने से उसकी गुणवत्ता बिगड़ गई है।

40 प्रतिशत तक नुकसान

महाकोशल-विंध्य में हाल में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से गेहूं, चना और मसूर की फसलों को नुकसान हुआ है। अंचल के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला, शहडोल, रीवा, सतना, सिवनी, बालाघाट और सीधी जिलों में 15 से 40 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। इन जिलों में सबसे अधिक दलहनी फसलें प्रभावित हुई हैं।

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास योजना को मंजूरी

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कृषि यंत्र सुधारने, चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना को स्वीकृति दे दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। कृषि यंत्रीकरण

में प्रशिक्षण से जहां युवा स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम होंगे। वहीं किसानों को भी आसानी से कृषि यंत्र मिल सकेंगे। सरकार ने योजना के लिए 22 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रदेश में तेल घानी बोर्ड गठित होगा: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साहू राठौर सकल तैलिक समाज, परिश्रमी-देशभक्त और राष्ट्रवादी समाज है। राज्य सरकार समाज के कल्याण और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान जंबूरी मैदान में राठौर साहू सकल तैलिक समाज के सामाजिक महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ कर्मा देवी की कृपा देश-प्रदेश पर बनी रहे और माँ सभी के जीवन में सुख-समृद्धि प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर एक सप्ताह में तेल घानी बोर्ड का गठन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि माँ कर्मा के तीर्थ-स्थल नरवरगढ़, मंदसौर के तेलिया तालाब सहित अन्य स्थानों को विकसित करने तथा अन्य मांगों की पूर्ति के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

भारतीय ग्रामीण जीवन शैली का बदलता स्वरूप

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) म. प्र.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के साथ रहना प्राकृतिक रूप से जीवन यापन करना तथा प्राकृतिक खानपान की पद्धतियां अपनाते हुए अपने भोजन में शामिल करना सदियों से भारतीय ग्रामीण जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रही हैं। लेकिन ग्रामीण जीवन शैली की पुरातन विरासत अपना अस्तित्व खो चुकी है। धीरे-धीरे शहरी सुविधाएं गांवों तक पहुंच चुकी हैं, जिससे निश्चित तौर पर ग्रामीण जीवन शैली मैं सुधार देखने को मिल रहा है।

कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भौतिकवादी जीवनशैली जीवन का एक अभिन्न अंग बनती जा रही है। इससे एक तरफ ग्रामीण जीवन जीना तो आसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर गावों में प्रकृति के साथ जीने की जो जीवनशैली थी वह खत्म हो चुकी है। इसके चलते गांव भी आज शहरों में पाई जाने वाली अनेक समस्याओं और बुराइयों से अछूते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के खानपान की पद्धतियां, उन्हें बनाने के तरीके तथा भोजन में शामिल विभिन्न प्रकार के अनाज, वस्तुएँ आदि आज धीरे-धीरे गौड़ हो चुके हैं। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्रों में गाय-भैंस का दूध मिट्टी से तैयार बोरसी में गोबर से बनाए गए उपले डालकर मिट्टी की ही बनी हाड़ी अर्थात हड़िया में गर्म किया जाता था। धीरे-धीरे करीब 3 से 4 घंटे जब दूध गर्म होता था तब दूध के अंदर की वसा मोटी परत के रूप में ऊपर आ जाती थी। दूध में यदि कोई बेड एलिमेंट होते थे तो उसे मिट्टी सोख लेती थी। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स दूध में मिश्रित हो जाते थे। इससे दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ उसकी पोषण वैल्यू और स्वाद में बहुत इजाफा होता था। लेकिन आज गांवों में दूध गर्म करने के लिए एलमुनियम-स्टील के बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इन धातुओं के तत्व दूध में मिश्रित होकर किडनी और लीवर जैसे मानव अंगों को खराब करने का काम कर रहे हैं।

हांड़ी में दूध गर्म करने के बाद इसे मिट्टी के बर्तनों में ही जामन लगाकर जमाया जाता था तथा सुबह मिट्टी के बर्तनों में ही हाथों से रई द्वारा चला कर इसका मक्खन तथा मट्ठा तैयार किया जाता था। जो कि स्वाद और पोषण में अच्छा होने के साथ-साथ ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता था। मट्ठा बिलोने वाली महिला का व्यायाम होने की वजह से उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता था।

गांवों में आटा भी पहले हाथ से चलने वाली चकिया से ही पीस कर तैयार किया जाता था। प्रतिदिन की जरूरत का आटा-दाना हाथ की चक्की से पीसकर तैयार कर लिया जाता था। जिसकी कल्पना करना आज मुमकिन नहीं है। भारतीय ग्रामीण जीवन शैली की ये कुछ ऐसी पद्धतियां थी जिससे हमें शुद्ध खानपान तो मिलता ही था, इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन, मोमोज जैसी चीजें चलन में आ चुकी है। एक दौर था जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्नेक्स के रूप में चना, मटर, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि को गांव में ही भाड़ पर भुनवाकर बखूबी खाया जाता था। यह स्वास्थ्य और सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे होते थे। अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के समय नाश्ते के रूप में दही, मट्ठा, गेहूं-चने की मिश्रित रोटी,

मक्खन/लोनी, दही, बाजरे की रोटी, आदि का प्रयोग किया जाता था। परंतु अब यह सब ग्रामीण नाश्ते की थाली से गायब हो चुके हैं। एक समय था जब गांव में चाय देखने को नहीं मिलती थी लेकिन आज वह जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आज खानपान की चीजों में स्वाद एक तरह से गायब हो चुका है। जबकि गांवों में चूल्हे की रोटी, देगची पर पकी दाल, छप्पर-बिटोरा तथा बुर्जी पर लगी लौकी, तोरई आदि की सब्जी के स्वाद जायका जिसने लिया है वही जानता है। ओखली में धनकुटे से कुटे हुए चावल हों या फिर गन्ने के रस में बनाई हुई रसखीर का स्वाद या फिर गरम गरम कोल्हू का गुड़, राव और शक्कर का स्वाद अपने आप में सब कुछ अनूठा था।

एक समय था जब गांवों में सर्दियों में अलाव/अगियाने पर शकरकंद और आलू भूनकर जब खाए जाते थे तो उसका स्वाद अपने आप में अनूठा होता था। समय के साथ आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है। देगची की जगह प्रेशर कुकर आ चुका है। पहले जब देगची में दाल पकाई जाती थी तो शुरू में दाल से निकलने वाले झाग और गंदगी को निकाल के बाहर किया जाता था। परंतु प्रेशर कुकर में यह सब गंदगी और झाग उसी में रह जाते हैं। यही कारण है कि आज जो घुटनों में दर्द की समस्या है, इन्ही वजह से बढ़ रही है।

गर्मियों के मौसम में चने और जौ से तैयार किए गए सत्तू प्राकृतिक रूप से बनाया गया शरीर को ठंडक देने वाला एक उत्तम पेय पदार्थ है। लेकिन ग्रामीण खानपान में इस सत्तू का स्थान बाजार में उपलब्ध अनेकों प्रकार की कोल्ड्रिंक्स ने ले लिया है। गांव में कोल्ड ड्रिंक तो हर घर पीने को मिल जाएगी परंतु सत्तू और छाछ का मिलना बहुत मुश्किल है। किसी समय में भारतीय ग्रामीण भोजन शैली में मोटे अनाज मिलेट की बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। लेकिन आज ग्रामीणों की थाली में इन मोटे अनाजों का उपयोग कम होता चला जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोक परंपराएं, लोक संगीत एवं गायन का भी अपना एक अलग महत्व रहा है। लेकिन आज यह सभी धीरे-धीरे विलुप्त के कगार पर आ गया है। आज गांवों में भी मनोरंजन के अनेक अन्य भौतिकवादी साधन अपना स्थान बना चुके हैं। जिसके चलते लोक संगीत, लोक गायन विलुप्ती के कगार पर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले अनेक स्थानीय खेल भी लगभग विलुप्त हो चुके हैं। यह सब हुआ है गांवों में भी भौतिक वादी संस्कृति के पैर पसारने के चलते। मिट्टी के घड़े का हम एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। पूरी गर्मी मिट्टी के घड़े में पानी भर के उपयोग किया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि आपको फ्रिज के पानी की जरूरत पड़े। मिट्टी के घड़े में पानी शीतल और मृदु होने के साथ ही साथ काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है।

प्राकृतिक जीवन शैली का कोई विकल्प न पहले था, ना आज है और ना आगे होगा। ऐसे में समाज का एक वर्ग प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक खानपान की लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देख रहा है। जिसके लिए फार्म टूरिज्म एवं गांव पर्यटन जैसी अवधारणा लेकर लोग आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में फार्म टूरिज्म शुरू भी हो चुका है, जहां जाकर शहरी संपन्न लोग कुछ दिन-रात बिताकर पुरातन ग्रामीण जीवन शैली का आनंद लेने के साथ ही परंपरागत ग्रामीण खानपान का स्वाद भी ले रहे हैं।

भूख के खिलाफ लड़ाई में अहम घर के बगीचे

घर में बगीचा भोजन की आपूर्ति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसका उद्देश्य आहार पैटर्न में बदलाव कर पोषण में सुधार करना है। घरेलू उद्यान बेहतर खाद्य सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं की उच्च आहार गुणवत्ता में योगदान करते हैं। ओडिशा राज्य की जंगली पहाड़ियां जहां भारत के कुछ सबसे कमजोर आदिवासी समूहों के घर हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि छोटे घर के बगीचे जिनमें बाजरा, दालें, ताजे फल और सब्जियां पैदा करके खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में, दुनिया भर में 82.8 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे थे और लगभग 3.1 अरब लोगों को स्वस्थ आहार नहीं मिला। वर्तमान समय में भारत एक मध्यम आय वाला देश होने के बावजूद, यह खाद्य सुरक्षा, कुपोषण तथा महिलाओं और बच्चों में बढ़ते एनीमिया के स्तर से जूझ रहा है। हाल के वर्षों में, इस बारे में अध्ययन किए गए, कि कैसे घर के बगीचे घरेलू स्तर पर अहम हैं, भूख से मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा, आहार गुणवत्ता और आय पर उनके असर को लेकर इसका दायरा सीमित हैं।

घर के बगीचे या होम गार्डन्स को लेकर किए गए शोध ने राज्य में आदिवासी समुदायों के लगभग 1,900 परिवारों को देखा। शोध से पता चला कि ओडिशा में इस बात के ठोस सबूत सामने आए कि घरेलू उद्यान इन ग्रामीण कृषक समुदायों में खाद्य सुरक्षा, आहार की गुणवत्ता और आय में सुधार कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं घर के बगीचे: एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी के शोधकर्ता और प्रमुख शोधकर्ता सिल्वेस्टर ओगुतु ने कहा कि घर में बगीचा होने से वार्षिक घरेलू उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। ओगुतु ने कहा, हमारे निष्कर्ष यह भी सुझाव देते हैं कि घर में बगीचा एक संसाधन के रूप में गरीब किसानों और कमजोर जनसंख्या समूहों के लिए गरीबी कम करने की रणनीति हो सकती है। इससे घरेलू उद्यानों को अपनाने वालों के बीच खाद्य सुरक्षा के बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने कहा, घर में बगीचा होने से मासिक प्रति व्यक्ति आय में 37 फीसदी की वृद्धि हुई और गरीबी के प्रसार में 11.7 प्रतिशत की कमी आई।

घर में बगीचों का उज्ज्वल भविष्य: एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी के कृषि अर्थशास्त्री, सह-शोधकर्ता जोनाथन मॉकशेल ने कहा कि 2017 में ओडिशा में आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को पढ़ाने या घर के बगीचों में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए गए। 2020 और 2021 के बीच घर में बगीचों के तीन चौथाई को पूरा किया गया।

मॉकशेल ने कहा, गृह उद्यान पोषण में सुधार के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी अहम हो सकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में भी योगदान दे सकते हैं, विशेष रूप से गरीबी, शून्य भूख और अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित लक्ष्यों को लेकर भी अहम है। सह-अध्ययनकर्ता जेम्स गैरेट ने कहा, भारत में घर के बगीचों को बढ़ावा देने से महिलाओं में एनीमिया जैसी व्यापक कुपोषण की समस्याओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। आहार की गुणवत्ता में सुधार करके जो आम तौर पर इनमें कम विविधता होती है। अनाज का उपयोग अधिक किया जाता है जबकि फलों और सब्जियों का सेवन कम होता है। भारत में एक कार्यक्रम का लक्ष्य घर में बगीचों को बढ़ाने के साथ 27,300 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचना है ताकि अत्यधिक पौष्टिक घर पर निर्मित खाद्य पदार्थों का उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिल सके। ताकि इससे उनके आहार की गुणवत्ता में सुधार करके उनके भोजन और पोषण सुरक्षा में सुधार किया जा सके।

शोध में कहा गया कि यह, नवीनतम शोध एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी और राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों पर एक सीजीआईएआर पहल का एक हिस्सा है, जो घर के बगीचों के फायदों पर शोध साक्ष्य को जोड़ने के लिए नीति बनाने, खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने में योगदान करने के लिए है। यह शोध एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी के कृषि अर्थशास्त्र जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में प्रकाशित किया गया है।

अमृत सरोवर योजनाः किसानों के लिए बन सकती है वरदान

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यही वजह है कि केंद्र ने ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाने के लिए अमृत सरोवर योजना बनाई है। इस योजना के तहत देश के गावों में हजारों तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों से सिंचाई तो होगी ही, साथ में मछली पालन करने से किसानों की कमाई भी बढ़ेगी।

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार इस साल 15 अगस्त तक 50 हजार सरोवर देश को समर्पित करेगी। इस योजना के पहले चरण में 40 हजार तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे देश को समर्पित किया जा चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने लांच किया था। इस योजना के तहत हरेक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के साथ- साथ उसका कायाकल्प किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाके में पानी की समस्या में कमी आएगी। साथ ही किसानों सिंचाई करने के लिए समय पर पानी मिल सकेगा।

सभी एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 11 महीने के अंदर ही लक्ष्य का 80 फीसदी काम पूरा हो गया है। जन भागिदारी के तहत देश में सरोवर बनाने के लिए 54 हजार से अधिक उपभोक्ता समूह बनाए गए हैं। इसी के जरिए तालाब बनाए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इस काम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारी लगे हुए हैं। सभी एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं। वहीं, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाके में पानी की समस्या कम होगी। साथ में किसान तालाबों में मछली पालन, बतख पालन, सिंघाड़े की खेती और मखाने की खेती कर अपनी इनकम भी बढ़ा कसते हैं।

इसमें सिंचाई की कम जरूरत होती है: बता दें कि देश में सबसे अधिक भूजल का दोलन फसलों की सिंचाई करने में होता है। पंजाब में 97 फीसदी भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इससे यहां पर जल संकट खड़ा हो गया है। कल ही खबर सामने आई थी कि भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार धान की जगह अन्य फसलों की खेती को बढ़ाने देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है। पंजाब सरकार का मानना है कि धान की फसल में बहुत अधिक पानी खर्च होता है। यदि इसकी जगह मक्का और कपास की खेती की जाए, तो भूजल स्तर में सुधार आएगा। क्योंकि इसमें सिंचाई की कम जरूरत होती है। अमृत सरोवर योजना से जहां एक तरफ भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ जलस्तर बढ़ने से खेती में भी उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे में यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

प्याज में अधिक उत्पादन के लिए कीट व्याधि का करे प्रबंधन डा अखिलेश

रीवा। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा म प्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डा अखिलेश कुमार ने बताया कि रीवा में प्याज की खेती ज्यादा क्षेत्र में की जाती है जिसमे मुख्य रूप से कीट व्याधि का प्रकोप होने पर प्याज का उत्पादन काफी प्रभावित होता है। प्याज में रीवा क्षेत्र में थ्रीप्स कीट का प्रकोप होता है जिसमे पत्तियां बीच से मुड़कर लटक जाती है और पत्तियों पर सफेद चमीकीले रंग के धब्बे दिखाई देते है जिसके नियंत्रण के लिए 4000 येलो ट्रैप प्रति एकड़ लगाना चाहिए साथ ही साथ इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल की 160 एमएल मात्रा के साथ 80 एमएल चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर आवसयकता अनुसार छिड़काव करे। दूसरा कीट कभी कभी दिखाई देता है जो प्याज की गांठ (बल्ब) से लेकर पत्तियों के अंदर पाया जाता है जिसे बल्ब वेधक कीट कहते है जिसके प्रबंधन के लिए लाइट ट्रैप एक एलइडी बल्ब 9 वॉट का प्रयोग प्रति एकड़ करते है और इंडोक्साकार्ब 15.8 ई सी की 500 मिली मात्रा प्रति हेक्टेयर व चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्याज का झुलसा रोग जिसमे पत्तियां ऊपर से सूख जाती है जिसके नियंत्रण के लिए क्लोरोथालोनिल 75 डब्लू पी की 800 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर चिपकने वाले पदार्थ के साथ या प्रॉपिकोनाजोल 25 ई सी की 500 मिली मात्रा प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। प्याज की फसल कमजोर होने पर एन पी के 19:19:19 की 100 ग्राम मात्रा प्रति टंकी मिलाकर 2 से 3 बार पूरे फसल में करना चाहिए।

देवास जिले में बांस के लिए होंगे विकासखंड स्तरीय जागरूकता शिविर

देवास में बांस के लिए होंगे विकास खंड स्तरीय जागरूकता शिविर

देवास। जागत गांव हमार

शासन द्वारा 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत देवास जिले में बांस का चयन किया गया है। जिले में बांस उत्पादन के पश्चात उसके उत्पाद बनाये जा रहे हैं। इन उत्पादों मांग देश एवं विदेशों में बढ़ रही है। जिले में एक लाख हेक्टेयर में बांस खेती की जाने की योजना है। 'एक जिला एक उत्पाद योजना 'के तहत देवास जिले में कृषि क्षेत्र अंतर्गत बांस रोपण का रकबा बढ़ाने हेतु जन जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने आगामी माह में बांस उत्पादन के संबंध में विकासखंड स्तरीय जन जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जिले में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विभिन्न विकासखंडों में यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है तथा सहयोगी विभाग के तौर पर वन विभाग (क्षेत्रीय), वन विभाग (सामाजिक वानिकी), कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, उद्यानिकी विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जनजाति कार्य विभाग मिलकर कार्य करेंगे । जिले में दिनांक 06 अप्रैल को बागली एवं कन्नौद जनपद पंचायत में, 12 अप्रैल को देवास एवं टोंकखुर्द जनपद पंचायत में तथा 13 अप्रैल को सोनकच्छ एवं खातेगांव जनपद पंचायत में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बांस रोपण के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

बांस रोपण योजना का प्रचार-प्रसार करें

बांस रोपण हेतु प्रचार-प्रसार एवं सम्पर्क - कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि बड़े कृषकों की पड़त भूमि पर बांस रोपण हेतु प्रचार-प्रसार करें तथा बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण योजना का भी प्रचार-प्रसार करें। स्व सहायता समूहों के माध्यम से बांस रोपण करें एवं बांस उत्पादक कृषकों व बांस उद्यमियों से चर्चा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाँस रोपण में कृषकों को आ रही कठिनाइयों पर चर्चा एवं निवारण हेतु रणनीति बनाकर निर्धारण करें। सामाजिक वानिकी अंतर्गत बांस पौधों की न्यूनतम दरों पर उपलब्धता हेतु रणनीति बनाएं । सी। एस। आर। फंड से बांस रोपण की संभावना पर चर्चा करें। देवास में बांस की मांग एवं आपूर्ति उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग बांस की मांग पर चर्चा करें । उन्होंने कहा कि बड़े कृषकों को सूची- राजस्व विभाग तैयार करें एवं एफ। आर। ए। अंतर्गत प्रदाय वन भूमि की मेड़ों पर बांस रोपण करवाएं। प्रत्येक पंचायत अंतर्गत बांस वाटिका का निर्माण भी करें। उन्होंने कहा कि इसमें सम्मिलित विभाग वन विभाग (क्षेत्रीय), वन विभाग (सामाजिक वानिकी), कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, उद्यानिकी विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जनजाति कार्य विभाग मिलकर कार्य करें।

लघु मशरूम उत्पादक प्रशिक्षण में किसानों को दी गई जानकारी

रीवा। कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा (म.प्र.) द्वारा भारत सरकार के कौशल विकास योजनान्तर्गत लघु मशरूम उत्पादक विषय पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण का आयोजन सम्पन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण नवयुवक, महिलायें एवं कृषक प्रतिभागी के रूप में सम्मिलत रहे। यह कार्यक्रम 1 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. पाण्डेय प्रमुख वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा ने अपने उद्बोधन में मशरूम की मॉग एवं पौष्टिक गुणों पर चर्चा करते हुऐ इसे व्यवसायिक रूप से अंगीकृत करने की सलाह प्रतियोगियों को दी। डॉ. के. एस. बघेल ने मशरूम उत्पदन से जुडे समस्त कार्यक्रम समस्त सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक ए. के. पटेल, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. किन्जल्क सिंह, डॉ. सी जे. सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. स्मिता सिंह, डॉ. संजय सिंह, संदीप शर्मा, एम के मिश्रा, मंजू शुक्ला, ऋषभ विश्वकर्मा उपस्थिति उल्लेखनीय रही आभार प्रदर्शन डॉ. संजय सिंह द्वारा किया गया।

नरवाई जलाने पर कृषकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन ने शुजालपुर तहसील के ग्राम अमलाय के कृषकों द्वारा नरवाई जलाने पर कृषकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि नरवाई न जलाने के लिए कलेक्टर श्री जैन द्वारा 01 मार्च 2023 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। इसके पश्चात भी जिले में शुजालपुर तहसील के ग्राम अमलाय के कृषकों द्वारा नरवाई जलाने का कार्य किया गया, जिले मे फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं की सेटेलाईट मॉनिटरिंग-2023 आईसीएआर क्रीम्स से प्राप्त डाटा अनुसार ग्राम अमलाय के कृषकों द्वारा नरवाई जलाने का कार्य किया गया, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 का उल्लंघन है। इसके लिए कलेक्टर ने कृषकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 7 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है।

गोबर से पड़ों के लाइलाज रोग को ठीक करने का फॉर्मूला दिया

हवन की भस्म का इस्तेमाल कैमिकल फर्टिलाइजर की तरह किया जा सकता हैः डॉ राम कृपाल पाठक

भोपाल। जागत गांव हमार

ऋषि-कृषि की अवधारणा पर आधारित इस पौराणिक खेती की विधा को आज के समय में ज्यादा कारगर माना जा रहा है जिसे जैव गतिशील कृषि एवं ग्राम नामकरण भी दिया गया है। इस विधि को अग्निहोत्र कृषि कहते हैं जिसका वेदों में भी उल्लेख मिलता है इसे अपनाने से पर्यावरण, कृषि व किसान सभी को लाभ के साथ-साथ स्वास्थ्य जीवन शैली में सुधार भी होती है। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से परंपरागत जैविक कृषि से जहाँ अपेक्षाकृत कम पैदावार प्राप्त होती है वही इस विधि से दोगुनी व गुणवत्तापूर्ण पैदावार प्राप्त होती है। इस विधि से चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, टमाटर, प्याज, गोभी, खीरा, आम एवं पपीता आदि विभिन्न प्रकार के अनाजों, सब्जियों व फलों की खेती की जा सकती है। अग्निहोत्र से सूर्य एवं चद्रंमा से विषेष प्रकार की ऊर्जा संरक्षित होती है जो मिट्टी को विभिन्न तत्वों से परिपूर्ण कर संस्कारित करती है तथा पेड़ पौधों की सेहत को संरक्षित व संवर्धित करती है।

डॉ राम कृपाल पाठक जाने-माने कृषि वैज्ञानिक हैं। वह एक खास किस्म के आंवले के जनक रहे हैं। इसे 'नरेंद्र' आंवला कहते हैं। यह देश में आंवले की सबसे प्रचलित किस्मों में से एक है। डॉ पाठक ने बेल की ऐसी प्रजातियां तैयार की हैं जिनमें एक-एक किलो के फ्ल होते हैं। उन्होंने पड़ों के लाइलाज रोग को गोबर से ठीक करने का फॉर्मूला दिया है। वह हवन की भस्म को खाद बताते हैं। प्राकृतिक, बायोडायनेमिक, ऋषि-कृषि, ऑर्गेनिक और नैचुरल इन सभी तरह की खेती पर एक साथ काम करने वाले वह पहले वैज्ञानिकों में से एक हैं। कृषि विज्ञान में न जाने कितने ही शोधार्थियों को उन्होंने गाइड किया है। ये वैज्ञानिक आज देश-विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। डॉ पाठक ने खेती के लिए प्राचीन तौर-तरीकों पर प्कोकस किया है। उन्होंने प्रकृति में पोषक तत्वों के विज्ञान पर रिसचज़ की है। वह दावे के साथ कहते हैं कि बिना केमिकल और फटिज़्लाइजर के बेहतरीन खेती संभव है। ब्रह्मांडीय ऊजाज़ में हर चीज को ठीक करने की कुव्वत है। उन्होंने खेती को अग्निहोत्र विज्ञान से जोड़कर अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि पहले जानबूझकर इसकी अनदेखी होती रही है। डॉ राम कृपाल ने प्राकृतिक खेती से जुड़े कई पहलुओं के बारे बताया।

वैज्ञानिक से कम नहीं थे हमारे विद्वान ऋषि-मुनि

इन दिनों प्राकृतिक खेती की खूब चर्चा है। इस तरह की खेती की हर विधा पर डॉ राम कृपाल पाठक ने गहरा अध्ययन किया है। वह दावे के साथ कहते हैं कि खेती को प्राकृतिक संसाधनों से बड़ी आसानी और लाभकारी तरीके से किया जा सकता है। पुराने समय से ऐसा होता आया है। डॉ पाठक कॉस्मिक एनजीज़ यानी ब्रह्मांडीय ऊजाज़ की बात करते हैं। उन्होंने इस पर जमकर अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि आप जंगलों को देखिए। वे अपने आप फलते-फूलते हैं। क्या उनमें बीमारियां नहीं होती होंगी। भला वहां कौन जाता है फर्टिलाइजर देने। हमारे ऋषि-मुनि बहुत विद्वान थे। वे साइंटिस्टों से कम नहीं थे। वे हवन करते थे। हवनों में भी अग्निहोत्र हवन का खास महत्व है। इससे खास तरह की एनर्जी बनती है। यह हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करती है। हवन की भस्म का इस्तेमाल कैमिकल फर्टिलाइजर की तरह किया जा सकता है।

होमा फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं पाठक

इस तरह से की जाने वाली खेती को होमा फार्मिंग कहा जाता है। डॉ राम कृपाल पाठक देश में उन गिने चुने वैज्ञानिकों में हैं जो इस तरह की खेती के एक्सपर्ट हैं। यूपी का राजभवन इसका उदाहरण है। यहां के उद्यान का प्रभार आरके पाठक के शिष्य पर है।
उद्यान पूरी तरह से प्राकृतिक है। उद्यान में नियमित रूप से हवन की भस्म का छिड़काव किया जाता है। इसके कारण पेड़ पौधे रोगमुक्त हैं।

गाय के गोबर से ठीक किया आम के पेड में गमोसिस रोग

डॉ पाठक कहते हैं कि प्रकृति की शक्ति गजब है। इसके लिए उन्होंने आम के पेड़ों में होने वाले एक रोग का जिक्र किया। इसका नाम गमोसिस है। कभी इसका इलाज बहुत टेढ़ी खीर हुआ करता था। दरअसल, आम का पेड़ जहां से कटता है वहां से गम निकलता है। इस गम को बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इससे पूरा पेड़ सूख जाता है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के इलाज के लिए कैमिकल फॉम्यूलेशन बनाया था। इसे पेड़ के उस हिस्से पर लगाया जाता था जहां से गम निकल रहा होता था। लेकिन, यह बहुत कारगर नहीं था। इससे आम पट्टी के किसान बहुत परेशान थे। फिर आरके पाठक ने सोचा कि क्यों न इसका इलाज पारंपरिक तरीकों में तलाशा जाए। वह काफी अध्ययन करने लगे। उन्हें पता चला कि पहले लोग गाय के गोबर को इसके लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भी वैसा ही किया। इसके अभूतपूर्व नतीजे निकले।

नरेंद्र आंवला के हैं जनक...

दरअसल, गाय के गोबर में एंटी बैक्टीयल और एंटी फंगल प्रॉप टीज होती हैं। 000

दरअसल, गाय के गोबर में एंटी बैक्टीयल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। पुराने जमाने में लोग घरों को भी इसीलिए गाय के गोबर से लीपते थे। जब गाय के गोबर को गम पर अप्लाई किया गया तो उसने बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन की ग्रोथ को रोका। इसे लेकर स्टडी को पब्लिश भी किया गया।

हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रेसीडेंट डॉ पाठक करीब 80 साल के हो चुके हैं। लेकिन, आज भी वह बहुत सक्रिय हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए वह हर समय तैयार रहते हैं। उनके बताए तरीकों से न जानें कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं। डॉ पाठक को एक खास किस्म के आंवले को तैयार करने का श्रेय जाता है। इसका नाम नरेंद्र आंवला है। आंवले के औषधीय गुणों के कारण यह काफी मांग में रहता है। नरेंद्र आंवला आंवले की उत्कृष्ट किस्मों में से है। इसी तरह डॉ पाठक ने बेल की ऐसी किस्मों को विकसित किया जिनमें एक-एक किलो के फ्रूल होते हैं। इस तरह के बेल फल का छिलका बहुत पतला होता है। पल्प बहुत ज्यादा होता है। इसकी मांग बहुत ज्यादा है। अग्निहोत्र के समय इससे ऑक्सीजन, इथाईलीन ऑक्साइड, प्रोपाइलइन ऑक्साइड एवं फार्म एल्डिहाइड उत्पन्न होती है। फार्म एलडिहाइड जीवाणु के खिलाफ प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करते हैं प्रोपाइल इन ऑक्साइड वर्षा का कारण बनती है। गाय की सींग से कीटनाशक बनाने की विधि: गाय के सींग को उसके गोबर की खाद और मिट्टी के साथ 40 से 60 सेंटीमीटर अंदर जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसे प्रायः शरद ऋतु में गाड़ा जाता है। शीत ऋतु तक उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वसंत ऋतु में निकालकर उसके 25 ग्राम हिस्से को 15 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में छिड़क दिया जाता है। यह उत्तम कोटि के कीटनाशक और रोगनाशक की तरह कार्य करता है।

हवनों में भी अग्निहोत्र हवन का खास महत्व है। इससे खास तरह की एनर्जी बनती है। यह हार्मफुल माइक्रोऑर्गनिज्म को खत्म करती है। हवन की भस्म का इस्तेमाल कैमिकल फर्टिलाइजर की तरह किया जा सकता है।

डॉ राम कृपाल पाठक जाने-माने कृषि वैज्ञानिक हैं। वह एक खास किस्म के आंवले के जनक रहे हैं। इसे 'नरेंद्र' आंवला कहते हैं। यह देश में आंवले की सबसे प्रचलित किस्मों में से एक है। डॉ पाठक ने बेल की ऐसी प्रजातियां तैयार की हैं जिनमें एक-एक किलो के फल होते हैं। उन्होंने पड़ों के लाइलाज रोग को गोबर से ठीक करने का फॉर्मूला दिया है। वह हवन की भस्म को खाद बताते हैं।

पंचमहाभूत एवं अग्निहोत्र से निकले खेती के समाधान

कृषक महेंद्र पिता जसमत सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत-मानकुंड, तहसील-हाटपिपल्या, जिला-देवास ने इसी विचार से जैविक खेती का रुख लिया। उनके अनुसार, खेतों में रसायनिक खाद के सतत बढ़ते उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तो होती, लेकिन लागत भी बढ़ रही थी और खेत की उर्वराशक्ति लगातार कम हो रही थी। इसलिए मैं अपनी साढ़े तीन एकड़ की जमीन में जैविक खेती करने को प्रेरित हुआ।

पहले साल जैविक खाद और वेस्ट डी-कंपोजर का उपयोग खेत में किया। जिससे उपज सामान्य रही। बाद में कृषि विभाग के संपर्क में आया और जैविक खेती से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। जिससे उत्पादन वृद्धि हेतु मुझे बीजोपचार से लेकर पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए समय-समय पर अनेक जैविक विकल्पों का सुझाव मिला। अब मैं मामूली सी लागत में ही गाय के गोबर, गौमूत्र तथा घर में उपलब्ध गुड़, छाछ, बेसन, अनाज, फलों को विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, गोवर्धन सजीव खाद, जैव रसायन, पंचगव्य बनाकर हानिकारक रसायनों से मुक्त खेती कर रहा हूं।

सूर्योदय व सायंकाल में कुछ विशेष मंत्रों के साथ हवन

श्री महेंद्र कहते हैं कि हाल ही में गेहूं में हुए इल्ली के प्रकोप की रोकथाम के लिए उन्होंने स्वनिर्मित मिट्टी द्रव्य रसायन का उपयोग किया जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले एवं फसल की गुणवत्ता भी तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर है। पिछले सीजन में सोयाबीन का भी 8-9 क्विंटल/एकड़ उत्पादन रहा और फसल का भाव भी अच्छा मिला। वे बताते हैं कि एक देसी गाय का गोबर 7 एकड़ में खेती के लिए पर्याप्त है और उनके पास 2 देसी गाय भी हैं। उन्होंने जैविक खेती में अग्निहोत्र का भी प्रावधान बताया। जिसमें सूर्योदय व सायंकाल में कुछ विशेष मंत्रों के साथ हवन करते हैं। इससे निकलने वाली ऊर्जा 8 एकड़ तक प्रभावी है। उन्होंने हवन से निकलने वाली अग्निहोत्र भस्म का भी खेतों के लिए विशेष महत्व बताया है।

केमिकल फ्री खेती की तरफ बढ़ा किसान!

जानें क्या है अग्निहोत्र भस्म जिसकी विदेशों में भी चर्चा

कानपुर के रहने वाले पंकज मिश्र अग्निहोत्र के बाद बची हुई भस्म को खाद में मिलाते हैं, जिससे मिट्टी को वह सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिसकी उसे जरूरत होती है। पंकज मिश्र अब वो अग्निहोत्र कृषि की तरफबढ़ रहे हैं और उन्होंने अग्निहोत्र फ्रेश फार्म नाम से एक स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर की है, जो कि अग्निहोत्र कृषि के द्वारा पैदा किए गए उत्पादों की मार्केटिंग करेगी। अग्निहोत्र फ्रेश फार्म के तहत रेस्टोरेंट और सेल्फ स्टोर्स की चेन कानपुर, लखनऊ, जयपुर और भोपाल में खोली जाएगी। खास बात तो यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने स्टार्टअप के तहत संस्था को बैंक के माध्यम से पूरी वित्तीय सुविधा प्रदान की है।

क्या है अग्निहोत्र?

अग्निहोत्र वेदों में बताई हुई एक हवन पद्धति है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त पर होती है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम भोपाल स्थित माधव आश्रम में माधव पोतदार के द्वारा की गई। अग्निहोत्र हवन जिसे करने के लिए तांबे या मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होती है। यह पात्र पिरामिड के आकार का होता है। जिसमें गाय के गोबर से बने हुए कंडे को रखा जाता है और उसमें साबुत चावल के साथ गाय का शुद्ध घी मिलाकर आहुति डाली जाती है। सूर्योदय के समय सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम... प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम' मंत्र का पाठ करते हुए आहुति दी जाती है। इसी प्रकार सूर्यास्त के वक्त अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इदं न मम व प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम मंत्रोच्चार कर आहुति की जाती है।

कैसे होती है अग्निहोत्र कृषि?

अग्निहोत्र हवन करने के बाद जो राख (भस्म) बचती है, उसका इस्तेमाल खेती करने के लिए होता है। साथ ही खेत में अग्निहोत्र हवन करने से शुद्ध वातावरण का घनत्व बढ़ता है, जिससे फसल में आपको आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम दिखेंगे। इस पद्धति में बोनी से कटनी तक खेत में अग्निहोत्र करना होता है।

अग्निहोत्र से बीजों उपचार भी

पंकज मिश्र का कहना है कि अग्निहोत्र से बीज जनित रोग भी नियंत्रित किये जा सकते हैं। इसके लिए गौमूत्र एवं अग्निहोत्र भस्म की आवश्कता पड़ती है। धान, फल, सब्जी के बीज गौमूत्र और अग्निहोत्र की भस्म के घोल में डुबो कर रखे जाते हैं। इसके बाद उनकी बोनी की जाती है। देश भर में कई किसान इस पद्धति को अपनाकर आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम हासिल कर चुके हैं। कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स में भी यह सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र कृषि पद्धति फसलों पर काफी असरदार है। साथ ही इसे करने के तरीके को माधव आश्रम, भोपाल ने पेटेंट भी कराया हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि अग्निहोत्र कृषि का डंका भारत ही नहीं ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों में भी बज रहा है। विदेशों से कई लोग इसके बारे में जानने के लिए उनके पास आते हैं। पंकज मिश्र का कहना है कि अग्निहोत्र फार्म स्टार्टप के जरिये शुद्ध तरीके से पैदा हुई फसल को इस्तेमाल कर लोगों को शुद्ध खाना देने उनका लक्ष्य है।

खेतों में अग्निहोत्र भस्म का इस्तेमाल

पंकज मिश्र बताते हैं कि अमावस्या व पूर्णिमा को आधे घंटे तक वो महा मृत्युंजय हवन करते हैं। इस दौरान मंत्रोच्चार से होने वाला स्पंदन खेती के लिए लाभप्रद पाया गया है। इस बीच दोनों दिनों के हवन से जो राख बनती है उसे अलग-अलग पात्र में रखा जाता है। फिर दोनों को मिलाकर खेतों में उनका छिड़काव कर दिया जाता है।

अग्निहोत्र के फायदे

- अग्निहोत्र की अग्नि वातावरण को पोषक और निरोग बनाती है।
- भस्म का उपयोग खाद की तरह किया जाता है।
- होम से जमीन का पुनर्जीवन होता है।
- अल्प या दीघ्रकाल की फसलों पर रोग नियत्रंण होता है।
- खेत में खरपतवारों पर नियंत्रण होता है।
- अग्निहोत्र से पालतू जानवरों को रोगों एवं बीमारियों से रक्षा करता है और उनके व्यवहार को पालक के अनुकूल बनाता है।
- अग्निहोत्र कृषि कार्य के लिए सकारात्मक वातावरण बनाता है।
- अग्निहोत्र प्रदूषण से वातावरण को मुक्त रखता है।
- अग्निहोत्र करने से भविष्य में आने वाली विपत्तियों जैसे बाढ़ भूकंप महामारियों से रक्षा करता है।
- होमा चिकित्सा प्रणाली का आधारभूत होम अग्निहोत्र है।

जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से फसलों को लाइलाज रोगों से स्थाई निजात दिलाने में मदद

मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लीनिक सेवा शुरू 15 जिलों में फसलों के उपचार की सुविधा

खेत में आईसीयू: मिट्टी और फसलों की लाइलाज बीमारियों का होगा उपचार

भोपाल। जागत गांव हमार

सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन किसान की फसलें भी हम इंसानों की ही तरह गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। ऐसे में फसलों की बीमारियों के उपचार के लिए अब न केवल एक क्लीनिक की सुविधा है, बल्कि इनकी लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए आईसीयू भी मौजूद है। समय के साथ बढ़ते प्रदूषण का असर पेड़-पौधों और फसलों की सेहत पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किसानों की फसलों को भी नई-नई बीमारियां घेरने लगी हैं। इंसानों एवं पशुओं की तरह ही वैज्ञानिक शोध के आधार पर फसलों की बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल काम करने लगे हैं। इसके तहत पेड़ पौधों और फसलों को होने वाले रोगों का इलाज खेत पर ही करने के लिए सरकार ने एक क्लीनिक शुरू किया है। इतना ही नहीं फसलों को होने वाले गंभीर रोगों के इलाज के लिए अब आईसीयू की सुविधा भी दी जा रही है। किसानों को अपने तरह की यह अनूठी सेवा यूपी में झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुरू की गई है।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और फसल रोग निदान परियोजना के प्रमुख डॉ प्रशांत जांभुलकर ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लीनिक सेवा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अपने तरह की यह अनूठी सेवा देश में पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 15 जिलों में किसानों को फसलों के उपचार की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को यह सुविधा देने के लिए किसान वाणी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें अब तक 250 किसान जुड़ चुके हैं। इन किसानों की कॉल पर फसलों के रोग का उपचार करने की सुविधा दी जाती है।

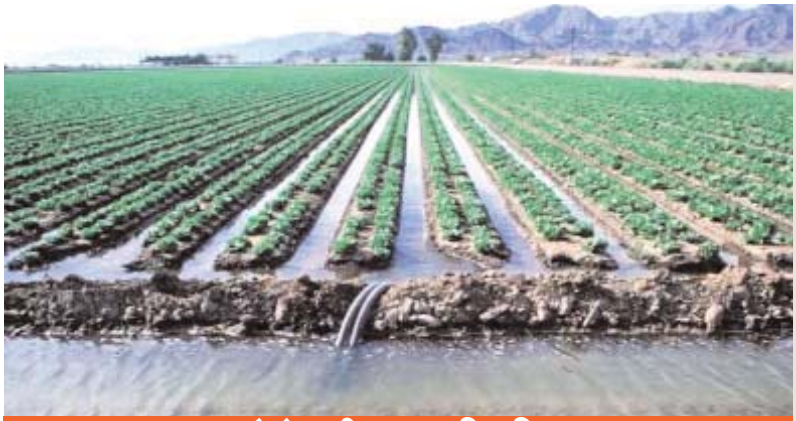

पहले रोग की पहचान, फिर निदान

डॉ जांभुलकर ने बताया कि किसान द्वारा खेत की मिट्टी या फसल में रोग लगने की सूचना मिलने पर मोबाइल क्लीनिक वैन खेत पर भेजी जाती है। इस वैन में मिट्टी और फसलों के सामान्य रोगों की पहचान करने से जुड़ी सभी तकनीक मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि फसल और मिट्टी में लगे रोग को मोबाइल वैन की छोटी लैब में पहचान करना जब मुमकिन नहीं होता है, तब फसल या मिट्टी के सैंपल को, विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित रोग निदान लैब में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह लैब फसलों की गंभीर बीमारियों की पहचान करने में सक्षम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसे फसलों का आईसीयू कहा जा सकता है। इस लैब में फसल या मिट्टी को लगे रोग की पहचान कर माकूल उपचार किया जाता है।

डीएनए परीक्षण करने की भी सुविधा

डा जांभुलकर ने बताया कि मिट्टी एवं फसलों के गंभीर रोगों की पहचान से पहले इनके सैंपल को कुछ समय के लिए आईसीयू के आइसोलेशन चैंबर में रखा जाता है। जिससे रोग के लक्षण उभर कर सामने आ सकें। लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान की जाती है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन में भी लक्षण नहीं उभरने पर सैंपल को इक्यूबेशन चैंबर में रख कर रोग जनित कारकों (बैक्टीरिया एवं वायरस) को उभरने का मौका दिया जाता है। इन कारकों की पहचान कर रोग का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद रोग के कारकों का डीएनए परीक्षण करके बीमारी के स्थाई इलाज का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने इस आईसीयू की तकनीकी कुशलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें रोगों की रोकथाम के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा सकती है। डा जांभुलकर ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से फसलों को लाइलाज रोगों से स्थाई निजात दिलाने में मदद मिलती है।

फसलों का होता है मुफ्त में इलाज

डा जांभुलकर ने बताया कि मोबाइल क्लीनिक हो या आईसीयू, फसल एवं मिट्टी के रोगों की पहचान के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसानों को फसलों के रोग निवारण के लिए सुझाई जाने वाली दवाओं का भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लैब में परीक्षण के बाद खेत में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को ग्रीन ग्रास या जिप्सम आदि का इस्तेमाल करने के लिए सुझाव दिया जाता है। किसानों को ग्रीन ग्रास के बीज या जिप्सम आदि कृषि विभाग द्वारा अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसानों को फसल एवं मिट्टी की चिकित्सा सुविधा लगभग मुफ्त में ही मिल जाती है।

गांव-गांव में तैनात होंगे प्लांट डॉक्टर

डॉ जांभुलकर ने कहा कि इस परियोजना के अगले चरण में लगभग हर गांव में एक प्लांट डॉक्टर तैनात किए जाने की योजना है। इसमें हर गांव के एक शिक्षित युवा को मिट्टी एवं फसलों की सामान्य बीमारियों की पहचान करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसे प्लांट डॉक्टर नाम दिया गया है। प्लांट डॉक्टर सीधे तौर पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे। किसानों से फसलों एवं मिट्टी के रोगों की सूचना मिलने पर ये रोग की पहचान कर इसकी प्राथमिक रिपोर्ट से कृषि वैज्ञानिकों को अवगत करा देंगे। इसके आधार पर किसानों को तत्काल रोग के उपचार की विधि बता दी जाएगी।

वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, भारत की पहली क्लोन गिर गाय का जन्म

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने इतिहास रच दिया है। दरअसल, 2021 में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर, साहीवाल और रेड-सिंधी जैसी देशी गायों की क्लोनिंग का कार्य शुरू किया था। इसी परियोजना के तहत 16 मार्च को गिर नस्ल की एक क्लोन बछिया का जन्म हुआ। इसका नाम गंगा रखा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने देसी गायों के संरक्षण और संख्या वृद्धि के लिए पशु क्लोनिंग तकनीक विकसित करने की शुरुआत की थी। इस काम के लिए गिर नस्ल का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये गाय अन्य नस्लों की अपेक्षा, बहुत अधिक सहनशील होती है। यह अत्यधिक तापमान व ठंड को आसानी से सहन कर लेती है। इनके अंदर अन्य गायों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है।

आईं कई चुनौतियां

वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख डॉ. नरेश सेलोकर ने बताया , करीब 15 सालों से भैंस के क्लोनिंग पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा गायों की भी क्लोनिंग करनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के पूर्व निदेशक डॉ. एमएस चौहान के नेतृत्व में गिर, साहीवाल और रेड-सिंधी जैसी देशी गायों की क्लोनिंग का कार्य शुरू हुआ। कैटल क्लोनिंग की काफी चुनौतियां थी। क्लोनिंग के लिए अंडे नहीं थे। ओपीयू तकनीक से अंडों को निकाला गया।

16 मार्च को मिली सफलता

डॉ. नरेश सेलोकर, ने बताया कि संस्थान ने क्लोनिंग के लिए तीन ब्रीड सलेक्ट की थी। साहीवाल में कुछ असफलताएं हाथ लगीं, लेकिन रिसर्च के बाद 16 मार्च 2023 को गिर गाय की क्लोन पैदा हुई। जन्म के समय गिर नस्ल की इस क्लोन बछिया का वजन 32। किलोग्राम था, वह पूरी तरह से स्वस्थ थी।

इयर डिवाइस, पशुओं की हर एक गतिविधि पर रखेगा नजर, बीमारी की भी देगा अपडेट

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का एक अहम योगदान है। देश के लगभग अधिकतर किसान खेती के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो वहीं देश का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन में लगा हुआ है, जिस वजह से आज भारत दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। जहां दूधारू पशु हमारी अर्थव्यवस्था में इतना योगदान दे रहे हैं तो वहीं यह हमें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पशुओं का ध्यान बेहतर तरीके से रखें। पशु बेजूबां हैं, जिस वजह से वह अपनी दर्द पीड़ा किसी को बता नहीं पाते हैं। जब तक हमें बीमारी का पता लगता है तो बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसी को देखते हुए कोच्चि स्थित कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप ब्रेनवायर ने पशुओं की देखभाल के लिए एक डिवाइस बनाया है जो उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा, साथ ही बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत अलर्ट कर देगा। यह बेहतरीन कारनामा करने वाले रोमियो पी. जेराई और श्रीशंकर एस. नायर हैं जो कि कंपनी के संस्थापक और सह-संस्थापक है।

ब्रेनवायर का पशु इयर डिवाइस

ब्रेनवायर कंपनी ने पशुओं की सुविधा के लिए एक इयर डिवाइस बनाया है, जिसे पशुओं के कान पर लगाया जाता है। डिवाइस पशु के कान पर लगाने के बाद आपको उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, गतिविधि निगरानी, ताप चक्र, मौसम निगरानी, पशु चिकित्सक सहायता आदि की जानकारी हर 10 सेकेंड में मिलती रहती है। इसके लिए ऐप भी विकसित किया गया है। साथ ही पशु के गर्भाधान की भी जानकारी आपको मिलती है।

आईओटी-आधारित डिवाइस

आईओटी-आधारित डिवाइस का उपयोग अब केरल और बाहर दोनों में 600 से अधिक गायों में किया गया है। डिवाइस की तैनाती के लिए महाराष्ट्र और कश्मीर की सरकारें ब्रेनवायर्ड के साथ बातचीत कर रही हैं। इस बेहतरीन तकनीक को यदि देश के सभी पशुओं में लगया जाता है तो, बीमारी से पशु मौत के आंकड़े कम होने लगेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)